भारतीय दलों का स्वरूप

प्रदोष कुमार

सरकार के गठन के साथ-साथ जनता में राजनीतिक जागरूकता लाने में राजनीतिक दलों की भूमिका प्रसांगिक है। साथ ही यह नागरिक समाज एवं राज्य के बीच सेतु के रूप में विद्यमान हैं। भारत में दलीय व्यवस्था का उदय लोकतांत्रिक व्यवस्था का केवल परिणाम नहीं अपितु उपनिवेश काल में राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआती दौर में ब्रिटिश साम्राज्य की एक दबाव समूह के रूप में भारतीयों के लिए ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी की मांग करती रही जिसने आगे चलकर जन आंदोलन का रूप ले लिया था।

लोकतंत्र किसी भी स्वरूप में राजनीतिक दल के बिना अकल्पनीय है। प्रोफेसर मुनरो के अनुसार लोकतंत्र है शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है दल प्रणाली के अभाव में इसका क्रियान्वयन असंभव है।ये असंख्य आकांक्षाओं का एक मूर्त रूप होता है। रजनी कोठारी दलीय प्रणाली को राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष राजनीतिक केंद्र की उपज मानते हैं। यह राजनीतिक केंद्र थे- सामाजिक ,आर्थिक रूप से संपन्न राजनीतिक अभिजात्य वर्ग, शहरी शिक्षित तथा मध्यम एवं उच्च वर्गों के उच्च जाति के लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक केंद्र का संस्थागत प्रकटीकरण था जो कालांतर में राजनीतिक व्यवस्था का आधार बना ।समाज के बदलते स्वरूप के साथ राजनीतिक दलों की

Scanned with CamScanner

प्रकृति में भी बदलाव आता चला गया। कोठारी के अनुसार दल प्रणाली की प्रकृति में बदलाव राज्य की परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या की रूपरेखा का परिणाम है।

भारत में दलीय व्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में जहां एक ओर राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि और संसदीय लोकतंत्र की मांग थी वहीं दूसरी ओर विशाल सांस्कृतिक, धार्मिक, अनेकता तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और उसमें परिवर्तन की मांग थी। भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है भारत का सामाजिक ,आर्थिक ढांचा, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश भौगोलिक स्थिति विकास दर तथा सबसे महत्वपूर्ण इसकी सामाजिक चेतना ने दलीय व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित किया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दो दशक के दौरान दलीय प्रणाली का एक दल प्रणाली के रूप में उल्लेख किया जाता है। जहां कांग्रेस केंद्रीय संस्था के रूप में विद्यमान है । मॉरिस जॉन्स के अनुसार भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक दल प्रभुत्व व्यवस्था दर्शाती है जहां कांग्रेस का वर्चस्व कायम है।भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ने जहां बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया वहां एक दलीय व्यवस्था का वर्चस्व कायम था। कांग्रेस के प्राप्त मतों का अन्य किसी भी दल के प्राप्त मतों के अंतर बहुत अधिक था इस अंतर के कई कारणों में प्रमुख थे उसकी असीम संगठन शक्ति, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, सम्मानित नेता ,स्पष्ट राजनीतिक मुद्दे साथ ही साथ संसद तथा राज्य विधानसभा में दोनों भारी जनसंख्या में सीट जीतने की उसकी क्षमता प्राप्ति से लेकर 1992 तक के राजनीतिक

Scanned with CamScanner

विकास में एक या दो बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद भारतीय राजनीति किसी नवीन दिशा की ओर मोड़ने की चेष्टा कर रही है परंतु इसने स्वपन जैसा प्रतीत क्षणिक परिवर्तन के बाद पुनः अपने स्वरुप को प्राप्त कर लिया। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप उसने विरोधी दल के साथ मिलकर सरकारों का गठन किया।। 60 के बाद वाले दशक में दल प्रणाली की प्रकृति में बदलाव रजनी कोठारी के अनुसार समय की मांग थी जिसने भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता वाली स्थिति से निकल कर उस स्थिति में प्रवेश किया जिसने जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने की प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई 1977 का आम चुनाव इंदिरा गांधी बनाम अन्य था जिसमें कांग्रेस की हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ। इस संगठन में कांग्रेस (ओ), जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी दल तथा कांग्रेस से बागी अन्य घटक दलों के साथ-साथ जगजीवन राम का (कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी) भी शामिल हुए। राज्य की रूपरेखा में ऐसा परिवर्तन आम जनता की राजनीतिक चेतना के साथ-साथ समाज राजनीतिक वर्गों के उदय का परिणाम था ।इसके साथ ही कांग्रेस की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा इंदिरा गांधी की के निरंकुश नेतृत्व से जन असंतोष बड़ा इसके अतिरिक्त नए ग्रामीण परिवेश ,पिछड़ी जातियों और वर्गों की अपनी अपनी समस्या, युवा वर्ग की नई चेतना आदि तत्व महत्वपूर्ण थे। उसकी ना सिर्फ राजनीति व्यवस्था से अलग मांगे और आकांक्षाएं थी बल्कि वे अपनी राजनीतिक

Scanned with CamScanner

परिभाषाओं का भी प्रयोग करना चाहते थे । जनता पार्टी की सरकार उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई तथा विविध सामाजिक समूह को एकीकृत करने में सक्षम नहीं हो सकी । परिणाम स्वरुप वह राजनीतिक स्थिरता एवं दिशाहीन शासन के रूप में सामने आई।

1980 के के मध्यावधि चुनावों में मध्यावधि चुनावों में पुनः कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि कांग्रेस पहले की तरह एक प्रभुत्व संपन्न दल के रूप में उभर कर सामने आई भारतीय दलीय व्यवस्था में अब क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी स्पष्ट दिखने लगी थी। निम्न जातियों एवं दलितों की भूमिका अधिक उजागर होने लगी थी जिसके परिणाम स्वरूप जनता दल बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। भारतीय राजनीति का नया दौर शुरू हुआ था। जहां पर जाति पर आधारित दलों का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी का कांग्रेस नेतृत्व एवं 1989 के आम चुनाव के साथ ही पुनः गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ जो सत्ता को 2 वर्षों तक भी नहीं खींच पाया । 1991 के बाद के आम चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका हो पाया। अब कोई भी दल अपने बलबूते सरकार बनाने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए 1991 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति का नया स्वरूप सामने आया। गठबंधन की राजनीति का स्वरूप 2009 के लोक सभा तक देखने को मिला।2014 के लोक सभा चुनाव में एन डी ए गठबंधन सत्ता में आई। जिसमे भाजपा बहुमत में रही। भारतीय दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था के साथ-साथ गठबंधन

Scanned with CamScanner

व्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है जहां राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों की भी अपनी भूमिका है।

Scanned with CamScanner